करने हेतु तैयार की गई है। परि-कल्पित रोजगार दो किस्म के हैं:—स्व: रोजगार उद्यमों की स्थापना और शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से लाभ-प्रद लोक परिसंपत्तियों का सृजन करके मजदूरी रोजगार का प्रावधान। यद्यपि योजना का मुख्य लक्षित ग्रुप शहरी निर्धन हैं किन्तु महिला लाभानुग्राही तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभानुग्राही विशेष लक्षित ग्रुप हैं।

(ग) ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

"राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड" का रुग्ण होना

1509. **श्री अनन्त राम जायसवाल :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 जनवरी, 1993 के "जनसत्ता" में "इस तरह डूबा राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम" नामक शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड को रुग्ण घोषित कर दिया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इसे पिछले सात वर्षों से लगातार हो रहे घाटे के कारणों का पता लगा लिया है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय परियोजना विकास लिमिटेड तुंगभद्रा परियोजना और इंदिरा सागर पावर हाउस के ठेके प्राप्त नहीं कर पाया, यद्यपि इसकी निविदा दर अन्य निविदाओं की दरों की तुलना में न्यूनतम थी; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी०के० थुंगन) : (क) जी हां।

(ख) यद्यपि नेशनल प्रोजेक्टस कंसट्रक्शन कारपोरेशन उत्पादक यूनिट, न होने के कारण, रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं आता है, फिर भी उक्त अधिनियम में निर्धारित मानदडों के अनुसार उसे रुग्ण यूनिट के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ग) कम्पनी को वर्ष 1989-90 से हानि हो रही है। ऐसी स्थिति के मुख्य कारण ये हैं—ऊपरी खर्चों पर अनुपात हीन उच्च व्यय, भारी ब्याज बोझ, कार्य करने में विलंब तथा कुछ कार्यों पर एन०पी०सी०सी० द्वारा उद्धृत की गई दरें गैर-मितव्ययी पाई गई हैं।

(घ) और (ङ) तुंगभद्रा परियोजना के लिये डाक के जरिये भेजे गये एन० पी०सी०सी० के टेंडर पर परियोजना प्राधिकरणों द्वारा विचार नहीं किया जा सका क्योंकि यह देरी से प्राप्त हुआ था। यद्यपि इंदिरा सागर परियोजना के विद्युतघर कार्यों के लिये एन०पी० सी०सी० का पहला टेंडर न्यूनतम था, लेकिन परियोजना प्राधिकरणों ने नये टेंडर आमंत्रित करने का निर्णय किया है। इस बार एन०पी०सी०सी० टेंडर न्यूनतम नहीं था।

Subansiri and Dihand Dam River Valley Projects

1510. SHRI TARA CHARAN MAJUMDAR: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Brahmaputra Board and the Ministry

of Water Resources have written to die State Government of Arunachal Pradesh for allowing the Brahmaputra Board to take up the work of subansiri and Dihand Dam River Valley Project under the Master Plan-I chalked out under the Brahmaputra Board Act, 1980; and

(b) if so, what are the details thereof and by when the work would start and the expenditure likely to be incurred on each project?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) and (b) Yes, Sir. Government of Arunachal Pradesh has been approached to allow Brahmaputra Board for carrying out survey and investigation to assess the impact *of* the Subansiri and Dih-ang projects on the environment and the oustees for planning the requisite remedial measures. These are needed for finalisation of the detailed project report and its sanction. Permission from the Government of Arunachal Pradesh is awaited.

Master plan submitted by Brahmaputra Board

1511. SHRI TARA CHARAN MAJUMDAR: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state the action taken on the Master Plan Part-I submitted by the Brahmaputra Board in December, 1986?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVE LOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K THUNGON): The Master Plan Part-I identifying short-term and long-term measures for control of floods, bank erosion, improvement of drainage in the Brahmaputra Valley, has been circulated to all the concerned state Governments and Central organisations by the Brahmaputra Board. Detaled surveys have to be carried out for preparation of specific schemes tnd their implementation.

Activities of Brahmaputra Board

1512. SHRI TARA CHARAN MAJUMDAR: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state the different activtiies per formed by Brahamputra Board dur ing the financial year 1992-93?

THE MINISTETR OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): During the year 1992-93 Brahmaputra Board, apart from continuing studies for identified Projects and updating of main master plans, envisages to complete preparation of Detailed Project Report for Pagladiya Dam. Survey and investigation for the preparation of Master Plans for 12 tributaries and 3 drainage schemes and one model tray for Hydraulic Research Institute.

Execution of Irrigation Projects in States

1513. SHRI DILIP SINGH JUDEV: Will the Minister of WATER RE SOURCES be pleased to state:

(a) whether any long term plan has been drawn up for the provision of irrigation by the end of the current century;

(b) if so the target set. Statewise:

c) the major and medium projects identified in different States. for execution during the period mentioned above; and

(d) the State-wise details thereof?